

प्रेषक,

अतर सिंह
संयुक्त सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग-4

देहरादून : दिनांक 19 अक्टूबर, 2015

विषय- वित्तीय वर्ष 2015-16 में जनपद-पौड़ी गढ़वाल के जिला चिकित्सालय परिसर में निर्माणाधीन शव-विच्छेदन गृह हेतु धनांवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-7प/1/श.वि.गृ./30/2007/21834, दिनांक 04.09.2015 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के जिला चिकित्सालय परिसर में निर्माणाधीन शव-विच्छेदन गृह के पुनरीक्षित आगणन ₹ 32.33 लाख के सापेक्ष वित्त विभाग की टी0ए0सी0 द्वारा औचित्यपूर्ण पायी गयी ₹ 32.35 लाख (₹ 32.14 लाख सिविल कार्यों हेतु तथा ₹ 0.21 लाख उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली-2008 के अनुसार कार्यों हेतु), जिसमें से शासनादेश संख्या-808/XXVIII-5-2007-145/2007, दिनांक 29.11.2007 के द्वारा पूर्व में अवमुक्त ₹ 11.71 लाख की धनराशि को समायोजित करते हुये अवशेष ₹ 20.00 लाख की धनराशि को वित्तीय वर्ष 2014-15 में शासनादेश संख्या-517/XXVIII-4-2015-87/2013, दिनांक 30.03.2015 द्वारा व्यय हेतु आपके निर्वतन पर अवमुक्त किया गया था। किन्तु विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के कारण तत्समय उक्त धनराशि का आहरण कर व्यय नहीं किया जा सका। अतएव शासनादेश संख्या-517, दिनांक 30.03.2015 को निरस्त करते हुए संस्तुत पुनरीक्षित आगणन ₹ 32.35 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त के सापेक्ष देय अवशेष धनराशि ₹ 20.00 लाख को इस वित्तीय वर्ष 2015-16 में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन पुनः आपके निर्वतन पर रखते हुए व्यय करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1. प्रश्नगत कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 में शासनादेश संख्या-517/XXVIII-4-2015-87/2013, दिनांक 30.03.2015 द्वारा ₹ 20.00 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी थी, जिसे विभागीय अधिकारियों की लापरवाही/उदासीनता के कारण तत्समय कोषागार से आहरित नहीं किया जा सका। अतः इस हेतु दोषी अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करते हुए संस्तुति सहित सुस्पष्ट आख्या/प्रस्ताव शासन को विलम्बतम् 01 माह के अन्दर शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
2. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
3. कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाये जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।
4. कार्य कराते समय लोक निर्माण विभाग के स्वीकृत विशिष्टियों के अनुरूप कार्य कराये तथा कार्य की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जाये। कार्य की गुणवत्ता का पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माण एजेन्सी का होगा। कार्य हेतु कार्यदायी संस्था से निर्धारित प्रपत्र पर अनुबन्ध भी अवश्य हस्ताक्षरित करा लिया जाय।
5. धनराशि तत्काल आहरित की जायेगी तथा तत्पश्चात निर्माण इकाई को उपलब्ध करायी जायेगी। स्वीकृत धनराशि का उपभोग प्रत्येक दशा में इसी वित्तीय वर्ष के भीतर सुनिश्चित किया जायेगा।

(2)

6. स्वीकृत धनराशि के आहरण से संबंधित बाऊचर संख्या एवं दिनांक की सूचना तत्काल उपलब्ध करायी जायेगी तथा धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका में उल्लिखित प्राविधानों में बजट मैनुअल तथा शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
7. आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/ अनुमोदित दरों में जो दरे शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से भी ली गयी हो, की स्वीकृत हेतु नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।
8. स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय।
9. कार्य करने से पूर्व स्थल का भली-भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भुगर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा ले। निरीक्षण के पश्चात् आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाये। कार्य की प्रगति की निरन्तर एवं गहन समीक्षा करते हुये कार्य को निर्धारित समयसारिणी के अनुसार समयबद्ध रूप से पूर्ण करते हुये भवन विभाग को हस्तगत कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। विलम्ब या अन्य किसी भी दशा में आगणन पुनरीक्षण पर विचार नहीं किया जायेगा। उक्त कार्य के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-475/XXVII(7)/2008, दिनांक 15.12.2008 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर कार्यदायी संस्था से एम0ओ0यू0 अवश्य हस्ताक्षरित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
10. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाए, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाए। निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से परीक्षण करा ली जाय, उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।
11. उक्त भवन के कार्यों को शीघ्र प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जाए ताकि लागत पुनरीक्षित करने की आवश्यकता न पड़े। स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति आख्या प्रत्येक दशा में माह की 07 तारीख तक निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।
12. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकताएँ तकनीकी दृष्टि को मध्य नजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।
13. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-2047/XIV-219(2006), दिनांक 30.05.2006 तथा किसी भी व्यय हेतु अधिप्राप्ति नियमावली वित्तीय संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 (लेखा नियम), आय-व्ययक सम्बन्धी नियम तथा अन्य सुसंगत नियम, (बजट मैनुअल) तथा शासनादेश संख्या-267/XXVIII(1)/2008 दिनांक 27.03.2008 आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
14. इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-12 के लेखाशीर्षक 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्याय-आयोजनागत, 01-शहरी स्वास्थ्य सेवायें, 110-अस्पताल तथा औषधालय, 03-शव विच्छेदन गृहों का निर्माण 24-वृहत निर्माण कार्य के नामें डाला जायगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0-226(P)/XXVII(3)/2015-16, दिनांक 15 अक्टूबर, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्न : अलॉटमेंट आई-डी।

भवदीय,

(अतर सिंह)

संयुक्त सचिव

क्रमशः.....3

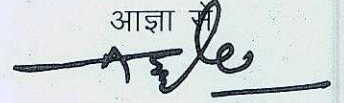
(3)

संख्या-1288(1)XXVIII-4-2015-87/2013, तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून ।
2. जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल ।
3. निदेशक, कोषागार, 23-लक्ष्मी रोड़, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
4. कोषाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल ।
5. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड ।
6. मुख्य चिकित्साधिकारी, पौड़ी गढ़वाल ।
7. परियोजना प्रबन्धक, अस्थाई निर्माण इकाई, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, पौड़ी गढ़वाल ।
8. बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून ।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0-3 / नियोजन विभाग / चिकित्सा अनुभाग-5 / एन0आई0सी0 ।
10. गार्ड फाईल ।

आज्ञा



(अतर सिंह)

संयुक्त सचिव ।